



संपादकीय

पारदर्शिता सुनिश्चित करने बड़ा कदम

जज के निवास पर भारी मात्रा में नोटों के मिलने के विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पदभार ग्रहण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपनी संपत्ति सार्वजनिक रूप से घोषित करने पर न्यायाधीशों ने सहमति जताई है। जजों की पूर्ण बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। यह खुलासा पूर्णतया स्वैच्छिक होगा। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सर्जीव खन्ना सहित सर्वोच्च न्यायालय के तैंतीस जजों में से तीस जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की। पूर्ण पीठ द्वारा संकल्प लिया गया कि जब भी कोई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किया जाए तो इसकी घोषणा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करनी चाहिए। हालांकि यह विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से आग लगने की घटना के बाद कथित तौर पर मिली नगदी के बाद यह बड़ा निर्णय लिया गया है। न्यायपालिका में पारदर्शिता और लोगों का विश्वास बनाए रखने की लिहाज से यह कदम दूरगामी साबित हो सकता है।

यह प्रस्ताव सभी भावी जजों पर लागू होगा। हाई कोर्टरे को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। 1977 में भी इसी तरह के प्रस्ताव रखे जाने के बावजूद इन पर अमल नहीं लाया जा सकता था। चूंकि बीते दिनों उठे विवादों को लेकर काफी चिंता व्यक्त की जा रही है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि इस घोषणा की उपेक्षा नहीं की जाएगी। यूं तो राजनेताओं के पास मिलने वाली आय से अधिक संपत्ति के बाद संपत्ति की घोषणा भले ही की जा रही है मगर उसे जनता द्वारा संदेह की नजर से ही देखा जाता है। दूसरे, उन्होंने यह संपत्ति कहाँ से और कैसे अर्जित की, यह सवाल खड़ा ही रहता है। जीवन साथी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जमा राशि या जमीन-जायदाद के मामले किसी से छिपे नहीं हैं। भ्रष्टाचार व काले धन को लेकर मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले जितनी मुखर थी, अब उतनी मौन ओढ़े है। बहरहाल, सबसे बड़ी अदालत ने अनाप-शनाप काला धन कबाड़ने वालों को बड़ा संकेत दिया है। इस मसले में सरकार से नाउम्मीद हो चुकी जनता का अदालत पर भरोसा तो बढ़ेगा ही, साथ ही नई उम्मीद भी जाग सकती है।

खड़ा ही रहता है। जीवन साथी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जमा राशि या जमीन-जायदाद के मामले किसी से छिपे नहीं हैं। भ्रष्टाचार व काले धन को लेकर मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले जितनी मुखर थी, अब उतनी मौन ओढ़े है। बहरहाल, सबसे बड़ी अदालत ने अनाप-शनाप काला धन कबाड़ने वालों को बड़ा संकेत दिया है। इस मसले में सरकार से नाउम्मीद हो चुकी जनता का अदालत पर भरोसा तो बढ़ेगा ही, साथ ही नई उम्मीद भी जाग सकती है।

साइबर युग में फंसती जा रही आने वाली पीढ़ी

– नृपेंद्र अभिषेक नृप

आज के समय में डिजिटल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। बच्चों और किशोरों के लिए इंटरनेट केवल एक मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह उनके मानसिक विकास, सामाजिक पहचान और मूल्यों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह डिजिटल युग हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित है?

क्या सोशल मीडिया कर्पनियां मुनाफे की दौड़ में बच्चों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही हैं? हाल के वर्षों में कई घटनाओं और शोध ने इस चिंता को और प्रबल कर दिया है कि किस प्रकार सोशल मीडिया के प्रभाव से किशोरों की मानसिकता और उनके व्यवहार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।

फिक्की-ईवाई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में डिजिटल मीडिया ने टेलीविजन को पछाड़कर मनोरंजन उद्योग में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला माध्यम बन गया है। भारत में 40 फीसद से अधिक मोबाइल फोन उपयोग का समय सोशल मीडिया पर बिताया जाता है। यह आंकड़ा बताता है कि इंटरनेट अब न केवल संचार का साधन है, बल्कि यह बच्चों की दुनिया का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। किशोरों के लिए सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जहां वे अपनी पहचान बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं और खुद को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन इस जुड़ाव के गंभीर परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

नेटफ्लक्स की चार-भागों वाली डॉक्यूमेंट्री ‘किशोरावस्था ‘ ने इस मुद्दे को और गहरा से उजागर किया है। इसमें एक 13 वर्षीय लड़के द्वारा अपनी सहपाठी की हत्या को घटना को दिखाया गया है। यह एक चरम मामला हो सकता है, लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन प्रभाव किस हद तक किशोर मन को प्रभावित कर सकता है। इंटरनेट पर मौजूद ‘टॉक्सिक मैस्कूलिनिटी’, घृणास्पद विचारधाराएं, और चरमपंथी विचारधाराएं किशोरों के मन में गहरी पैठ बना सकती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्मम का एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं की रुचि के अनुसार कंटेंट प्रदर्शित करता है। इस एल्गोरिदम का उद्देश्य अधिक से अधिक उपयोगकर्ताओं को प्लेटफार्म पर बनाए रखना है, भले ही इसके परिणाम किशोरों की मानसिकता पर नकारात्मक हों।

एक बार अगर कोई किशोर किसी विशेष प्रकार की सामग्री देखने लगता है, तो एल्गोरिदम उसे लगातार उसी तरह की सामग्री दिखाने लगता है। यह प्रक्रिया किशोरों को ‘रेबिट होल’ में धकेल सकती है, जहां वे खुद को एक अंधकावमय और हानिकारक डिजिटल दुनिया में फंसा पाते हैं। जब भी किशोरों के गलत कार्य की बात होती है, तो स्वाभाविक रूप से माता-पिता पर जिम्मेदारी आती है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या माता-पिता अकेले ही इस समस्या को हल कर सकते हैं?

ऑनलाइन प्लेटफार्मम पर बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी रखना आज के दौर में अत्यंत कठिन हो गया है। बच्चे अक्सर अपने माता-पिता से छुपाकर उम्र से बड़ी उम्र का प्रमाण देकर प्रतिक्रियाओं को पार कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ऐसे नियम व्यावहारिक रूप से प्रभावी नहीं हो सकते, क्योंकि किशोर अक्सर तकनीकी उपायों से इन प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकते हैं। यह समस्या केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर नीति-निर्माण और सामाजिक चेतना का भी विषय है। फेसबुक की पूर्व कर्मचारी फ्रांसेस हॉगन ने 2021 में इस बात का खुलासा किया था कि कंपनी के आंतरिक अध्ययन से यह सामने आया कि सोशल मीडिया पर मौजूद चरमपंथी विचारधाराएं, आत्मघाती प्रवृत्तियां, और अवसादग्रस्त करने वाली सामग्री किशोरों के लिए हानिकारक साबित हो रही हैं। इसके बावजूद, कंपनी ने अपने मुनाफे को प्राथमिकता दी और इन खतरों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इन प्लेटफार्मों की जवाबदेही तय की जाए। इस गंभीर समस्या का समाधान केवल व्यक्तिगत प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यापक सामाजिक और सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सबसे पहले, कानूनी नियमन के तहत सरकारों को सोशल मीडिया प्लेटफार्मस के लिए सख्त नियम लागू करने होंगे, ताकि वे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। उदाहरण के लिए, आयु सत्यापन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया आवश्यक है, जिससे नाबालिगों को अनुचित सामग्री से बचाया जा सके और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके। इसके साथ ही, शिक्षा और जागरूकता भी इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

विचार

यह भी दिलचस्प है कि बड़े और मलाईदार पदों पर बैठे एससी/एसटी के लोग उच्च और महंगे शिक्षा संस्थानों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलावा कर उसी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिसका मकसद आदिवासियों और दलितों की मलाई और तरक्की था, लेकिन इसने गिने-चुने लोगों को फायदा पहुंचाया है। इसकी वजह से जाति-व्यवस्था के समर्थक जातीय बंटवारे को बनाए रखने में सफल रहे हैं, जो आदिवासी और दलित हितों के लिए नुकसानदेह है। एससी/एसटी पर क्रीमी लेयर के विरोध में कथित रौबदार दलित आदिवासियों ने आवाज बुलंद की तो आम गरीब आदिवासी सड़कों पर उमड़ पड़े जबकि कथित अभिजात्य हो चुकी उनकी संतान सड़कों की बजाय उस समय महंगे कोरिंग संस्थानों में पढ़ रही होगी।

आरक्षण भोगी अभिजात्य वर्ग और अंबडेकर

डॉ. ब्रह्मदीप अलूनै

अंबेडकर भारत के संभवतः सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे और विशिष्ट अकादमिक डिग्री हासिल करने वाले शख्सियत थे। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बन सकते थे, लेकिन यदि उन्हें यह पेशकश की गई होती तो वे इसे शायद ही स्वीकार करते। इस बात की पूरी संभावना है कि इससे वे यह कह कर इंकार कर देते कि उनकी जगह किसी वंचित वर्ग के व्यक्ति को यह पद दिया जाए तो ज्यादा लाभदायक होगा। डॉ. अंबेडकर की सामाजिक न्याय की स्थापना के आग्रह के प्रति गहरा सम्मान दिखाते हुए ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश बी.आर.गवई ने कहा, ‘मैं डॉ. अंबेडकर के कारण सुप्रीम कोर्ट का जज हूं। डॉ. अंबेडकर के कारण मैं पढ़ता था। इस पद तक पहुंच सका।’ न्यायाधीश भी दलित समुदाय से ही उच्चतम न्यायालय में आगे बढ़ेंगे। वे अगले महीने यानी मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और दलित समुदाय से इस पद तक पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे।

दरअसल, आरक्षण को लेकर डॉ. अंबेडकर की स्पष्ट सोच थी कि यह वंचित वर्ग के लिए सामाजिक और आतथक समानता प्राप्त करने का एक संविधानिक अधिकार है। जस्टिस गवई ने कहा कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों को अंबेडकर की वजह से पहचान मिली। आजादी के आठवें दशक में प्रवेश कर चुके भारत में आज भी हाशिए पर पड़ा समाज अपनी मूलभूत जरूरतों और दो सजा की रोटी के लिए संघर्षरत है। उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आई है, और वह बढ़ कर करोड़ों में चली गई है। इसके बाद

भी कि एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण राजनीति से सरकारी नौकरी तक देश में लागू है और अब यह सामान्य गरीब वर्ग तक भी पहुंच गया है। भारतीय संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी, उसका उद्देश्य केवल कमजोर और दबे-कुचले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। डॉ. अंबेडकर का उद्देश्य एक समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना था और आरक्षण का प्रयोग तब तक किया जाना चाहिए जब तक समाज में वास्तविक समानता नहीं आ जाती। आरक्षण को एक स्थायी व्यवस्था न मानते हुए डॉ. अंबेडकर ने इसे एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा था। उनके लिए यह आरक्षण और उससे होने वाले विकास के द्वार किसी परिवार तक सीमित नहीं थे। यह समूचे समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले थे। लेकिन डॉ. अंबेडकर के उद्देश्य के इतर एससी/एसटी का आरक्षण तब विवादों में गिर गया जब राजस्थान में भील बनाम मीणा और बिहार में दलित बनाम महादलित का नारा बुलंद हुआ। दलित अनुसूचित जातियों की आबादी की बात की जाए तो ये भारत की कुल आबादी का साढ़े सोलह फीसद हैं।

भारत में आदिवासियों की आबादी तकरीबन ग्यारह करोड़ है। यह देश की कुल आबादी का साढ़े आठ फीसद है। आदिवासियों को भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। बीसवीं सदी की शुरु आत में दलित और आदिवासियों की सामाजिक शैक्षिक और आतथक स्थिति एक जैसी ही थी। गिने-चुने लोग ही थे। जो गिरी हुई



हालत से ऊपर उठ सके थे। 21वीं सदी में यह स्थिति बदली है। आरक्षण से आदिवासियों और दलितों के एक तबके को फायदा हुआ है, और अस्तित्व के लिए उनकी लड़ाई आसान हुई है। आदिवासियों और दलितों के एक तबके ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग उसी हालत में हैं, जिस स्थिति में वो आज आरक्षण की नीति बनाई गई है, ये उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाती आ रही है। जो इसका लाभ लेकर आगे बढ़ चुके हैं। नतीजा यह है कि दलितों और आदिवासियों में भी एक छोटा तबका ऐसा तैयार हो गया है, जो अमीर है। और जिसे व्यवस्था का लगातार फायदा हो रहा है। कानून बनाना विधायिका का काम है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात सहमत है कि एससी, एसटी आरक्षण में बदलाव होना चाहिए और इसमें क्रीमी

लेयर का प्रावधान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त, 2024 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण बारे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि सरकार इन समुदायों के आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। क्रीमी लेयर से मतलब उस वर्ग से है, जो आतथक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के एससी/एसटी आरक्षण में कोटा लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। इस दौरान नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफबताया था। 2018 में भी ऐसा ही फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का नियम लागू होगा। जस्टिस नरीमन ने कहा था ‘आरक्षण की व्यवस्था का मकसद नागरिकों के बीच पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है, जिससे कि वे भारत के अन्य नागरिकों की तरह समानता के आधार पर हाथ से हाथ मिला कर चल सकें।’

यह भी दिलचस्प है कि बड़े और मलाईदार पदों पर बैठे एससी/एसटी के लोग उच्च और महंगे शिक्षा संस्थानों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलावा कर उसी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिसका मकसद आदिवासियों और दलितों की

भलाई और उनकी तरक्की था, लेकिन इसने गिने-चुने लोगों को फायदा पहुंचाया है। इसकी वजह से जाति-व्यवस्था के समर्थक इस जातीय बंटवारे को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं, जो आदिवासी और दलित हितों के लिए नुकसानदेह है। एससी, एसटी पर क्रीमी लेयर के विरोध में कथित रौबदार दलित आदिवासियों ने आवाज बुलंद की तो आम गरीब आदिवासी सड़कों पर उमड़ पड़े जबकि कथित अभिजात्य हो चुकी उनकी संतान सड़कों की बजाय उस समय महंगे कोरिंग संस्थानों में पढ़ रही होगी। डॉ. अंबेडकर ने कल्पना की थी कि आरक्षण की मदद से आगे बढ़ने वाले दलित और आदिवासी अपनी बिरदरी के दूसरे लोगों को भी समाज के दबे-कुचले वर्ग से बाहर लाने में मदद करेंगे। मगर, हुआ यह है कि तरक्की याफता आदिवासियों और दलितों का यह तबका, सामाजिक तौर पर खुद को ऊंचे दर्जे का समझने लगा है।

आदिवासियों और दलितों की यह क्रीमी लेयर बाकी दलित आदिवासी आबादी से दूर हो गई है। डॉ. अंबेडकर ने एक ऐसे फॉर्मूले की आवश्यकता पर बल दिया था, जो अवसर की समानता को उन समुदायों के लिए आरक्षण प्रदान करने के साथ संतुलित कर सके, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से प्रशासन से बाहर रखा गया था। अभी भी दलित आदिवासियों का बड़ा तबका आरक्षण के फायदों से दूर है और उन्हें इसका फायदा तब ही मिल पाएगा जब वे आरक्षणभोगी अभिजात्य वर्ग को चुनौती देने का साहस करेंगे। डॉ. अंबेडकर को भी इस अभिजात्य वर्ग की कल्पना रही होगी। इसीलिए उन्होंने अपने जीवनकाल में ही एक सम्मेलन में आरक्षण समाप्त करने की बात कह दी थी।

वक्फ संशोधन के विरुद्ध याचिकाओं की प्रतिस्पर्धा शुरू

अवधेश कुमार

वक्फ संशोधन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं की प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। इस संशोधन के दोनों सदनों में पारित होने के अगले दिन से ही उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं जाने लगीं। एक साथ तीन तलाक, नागरिकता संशोधन कानून और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरुद्ध भी हमने यही देखा। इन सभी मामलों की न्यायिक परिणति देश के सामने है।

हमारे सामने दो दृश्य हैं।। लोक सभा में बहस के पूर्व सभी पार्टीयों ने न्दिय जारी कर दिया था। राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट घोषणा की कि सांसद स्वतंत्र हैं, द्दिप नहीं हैं, वे जैसे चाहें मतदान करें। इसके बावजूद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संख्या से ज्यादा मत विधेयक के समर्थन में आए। इसके कोई निहितार्थ हैं या नहीं? दोनों सदनों में बहस और मतदान पड़ेगा। संसद में समर्थन और विरोध, दोनों में मुसलमान उतरे। उन दो दिनों में समर्थकों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। अलग-अलग धार्मिक संस्थाओं और संगठनों ने खुल कर विधेयक का समर्थन किया। इममें वे मुस्लिम मजहबी नेता और संस्थाओं के प्रमुख भी शामिल थे जो पहले वक्फ में किसी प्रकार के

संशोधन का घोर विरोध करते थे। ऐसे विषयों पर सुधार और परिवर्तन के संवैधानिक कानूनी कदमों के विरुद्ध प्रचार और रोकने की कोशिश पहली बार नहीं है। वक्फ कानून, उससे संबंधित बोर्ड और ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण को मुस्लिम वोट पाने की नीति के तहत सुपर सरकार, सुपर प्रशासन और सुपर न्यायपालिका की भूमिका दे दी गई थी, उस दांचे में लाभान्वितों तथा आनंद सुख भोगने वालों के अंदर छटपटाहट स्वाभाविक है। वक्फ कानून में संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए था या संशोधन में क्या असंवैधानिक, इस्लाम विरोधी, मुस्लिम विरोधी है, इसका तथ्यात्मक उत्तर विपक्ष के किसी नेता द्वारा संसद में नहीं मिला। जब एक सदस्य ने कहा कि मुसलमान कानून को नहीं मानेगा तब गृह मंत्री ने कहा कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है, सबको मानना पड़ेगा। संसद द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत पारित कानून भारत के सभी क्षेत्रों और व्यक्तियों पर लागू होता है। कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने लोक सभा में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया का बहुमत के द्वारा संविधान का अतिक्रमण और लोकतंत्र का गला घोटने के समान बता दिया।



लोक सभा में अमित शाह ने रिकॉर्ड रखते हुए बताया कि संप्रग सरकार ने 2013 में चार घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पास कर दिया था जबकि इस बार दोनों सदनों में करीब 27 घंटे से ज्यादा का समय लगा। वक्फ में जिस तरह पूरे देश में संपत्तियों का दावा किया, कब्जे में लिया उसकी अनेक कथाएं रिपोर्टों में सामने हैं। यह कैसी संवैधानिक व्यवस्था थी जिसमें वक्फ किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा आप नहीं जा सकते। ट्रिब्यूनल बरसों लगा देगा और फैसले को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते यानी आपकी संपत्ति गई। इसमें हिन्दू और मुसलमान, दोनों के साथ सार्वजनिक सरकारी संपत्तियां भी शामिल हैं। गृह मंत्री ने सदन में रिकॉर्ड पर कहा कि कोई गांव या शहर से बाहर नौकरी करने चला गया और उसकी संपत्ति वक्फ कर दी गई।

वक्फ में कोई बदलाव नहीं है। किंतु हम अपनी संपत्ति वक्फ में रजिस्ट्री करा सकते हैं, दूसरे की संपत्ति पर कैसे दावा कर सकते हैं? सरकार कैसे संपत्ति वक्फ कर सकती है? यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सच्चर आयोग की नियुक्ति और उसकी रिपोर्ट के बाद पूरे देश में अलग से इस्लामी ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक संपत्ति वक्फ बोर्डे को दी। हमारी, आपकी या किसी मंदिर की जमीन के कागजात, राजस्व आदि का विषय जिला कलेक्टर के अधीन होगा किंतु वक्फ का नहीं हो तो कैसे इसे कानून का पालन माना जाएगा? वक्फ इस्लाम का अंग है, लेकिन भारत के संविधान और कानून के तहत सरकारों द्वारा गठित वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल इस्लाम का विषय नहीं हो सकता। उसे संविधान और कानून के अंतर्गत ही काम करना होगा। कोई संपत्ति जिस उद्देश्य के लिए वक्फ हुई, उसका उपयोग उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं तथा वक्फकर्ता ने? स्वेच्छा से ऐसा किया या दबाव डाल कर कराया गया इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी प्रशासन की है। जिस संस्था में लगभग 41 हजार विवाद हैं और उनमें 10 हजार मुसलमानों द्वारा किए गए उसे कायम नहीं रखा जा सकता

था। वास्तव में वक्फ कानून में संशोधन एक लोकतांत्रिक और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध, मजहब का अंग न होते हुए भी इस्लाम के नाम पर कुछ शक्तिशाली प्रभुत्वशाली मुस्लिम पुरुषों में आने के बाद सच्चर आयोग की नियुक्ति और उसकी रिपोर्ट के बाद पूरे देश में अलग से इस्लामी ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक संपत्ति वक्फ बोर्डे को दी। हमारी, आपकी या किसी मंदिर की जमीन के कागजात, राजस्व आदि का विषय जिला कलेक्टर के अधीन होगा किंतु वक्फ का नहीं हो तो कैसे इसे कानून का पालन माना जाएगा? वक्फ इस्लाम का अंग है, लेकिन भारत के संविधान और कानून के तहत सरकारों द्वारा गठित वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल इस्लाम का विषय नहीं हो सकता। उसे संविधान और कानून के अंतर्गत ही काम करना होगा। कोई संपत्ति जिस उद्देश्य के लिए वक्फ हुई, उसका उपयोग उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं तथा वक्फकर्ता ने? स्वेच्छा से ऐसा किया या दबाव डाल कर कराया गया इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी प्रशासन की है। जिस संस्था में लगभग 41 हजार विवाद हैं और उनमें 10 हजार मुसलमानों द्वारा किए गए उसे कायम नहीं रखा जा सकता था। वास्तव में वक्फ कानून में संशोधन एक लोकतांत्रिक और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध, मजहब का अंग न होते हुए भी इस्लाम के नाम पर कुछ शक्तिशाली प्रभुत्वशाली मुस्लिम पुरुषों में आने के बाद सच्चर आयोग की नियुक्ति और उसकी रिपोर्ट के बाद पूरे देश में अलग से इस्लामी ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक संपत्ति वक्फ बोर्डे को दी। हमारी, आपकी या किसी मंदिर की जमीन के कागजात, राजस्व आदि का विषय जिला कलेक्टर के अधीन होगा किंतु वक्फ का नहीं हो तो कैसे इसे कानून का पालन माना जाएगा? वक्फ इस्लाम का अंग है, लेकिन भारत के संविधान और कानून के तहत सरकारों द्वारा गठित वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल इस्लाम का विषय नहीं हो सकता। उसे संविधान और कानून के अंतर्गत ही काम करना होगा। कोई संपत्ति जिस उद्देश्य के लिए वक्फ हुई, उसका उपयोग उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं तथा वक्फकर्ता ने? स्वेच्छा से ऐसा किया या दबाव डाल कर कराया गया इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी प्रशासन की है। जिस संस्था में लगभग 41 हजार विवाद हैं और उनमें 10 हजार मुसलमानों द्वारा किए गए उसे कायम नहीं रखा जा सकता था।

मुद्रा योजना विकसित भारत तक ले जाने वाला सोपान

अखिलेश झा

विकसित भारत के लक्ष्य में जितनी बड़ी भूमिका बड़े उद्यमों की है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका छोटे एवं मझोले उद्यमों की भी। समावेशी विकास, गांवों-कस्बों में खेती से इतर रोजगार के अवसर के सृजन, किसानों के लिए मूल्य-संवर्धित सेवाओं के विकल्प और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अपेक्षित पहल थी छोटे-मझोले उद्यमों के लिए सुलभ वित्तपोषण की। इस अपेक्षा को यथार्थ में बदला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने, जो अपनी सफलता का आज पहला दशक पूरा कर रही है।

2015 में शुरू हुई ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत अबतक 52 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। इस योजना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दस करोड़ से भी अधिक नये कारोबारी दिए हैं, जो प्रतिशत में 20 से भी अधिक हैं। कुल ऋणालाभियों में बदला प्रधानमंत्री को दिया गया कुल ऋण दस लाख करोड़ से भी अधिक

का है। ये आंकड़े न सिर्फ भारतीय उद्यम के बदलते चेहरे को दर्शाते हैं, बल्कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की प्रगतिशील सोच एवं पहुंच को भी दिखाते हैं।

इस योजना के तहत पचास हजार रु पये के ऋण से लेकर बीस लाख रु पये तक के ऋण न सिर्फ भारतीय बाजार में नये उद्यमों और नये उद्यमियों के लिए जगह बना रहा है, बल्कि रोजगार के लिए भी करोड़ों अवसर पैदा कर रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2015 से 2018 के बीच तीन वर्षों में लगभग 1.12 करोड़ नये अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित हुए थे।

इस दौरान लगभग 5.55 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए गए थे इस योजना के तहत। यदि इस सह-संबंध को अवतक दिए गए 32.40 लाख करोड़ के ऋण के अनुसार देखा जाए, तो पिछले एक दशक में लगभग 7 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वजह से। मुद्रा योजना ने न सिर्फ उद्यम का स्वरूप बदला है, उद्यमिनि बैंकों की प्रोफाइल में गुणात्मक परिवर्तन किए हैं।

इस योजना के तहत लगभग 35 करोड़ महिलाओं के खाते में ऋण दिए गए हैं। इस तरह मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी उद्यमियों में महिलाओं का प्रतिशत दो तिहाई से भी अधिक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारतीय समाज-व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी इंगित करता है।

सामाजिक वर्ग के हिसाब से देखा जाए, तो इस योजना के तहत 8.5 करोड़ ऋण के खाते अनुसूचित जनजातियों के थे, लगभग 3 करोड़ अनुसूचित जनजातियों के और 14 करोड़ से भी अधिक खाते अन्य पिछले वर्ग के उद्यमियों के थे।

इस योजना के तहत 5.6 करोड़ उद्यमी अल्पसंख्यक थे, जिन्हें लगभग 3 लाख करोड़ रु पये का ऋण बैंकों द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सफलता एवं लोकप्रियता की वजह समझनी हो, तो एक आंकड़ा इसे सबसे बेहतर स्पष्ट कर देता है। इस योजना के तहत 52 करोड़ बैंक खातों के लिए 33.19 लाख करोड़ रुपये के ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए 2015 से अभी तक। उस 33.19 लाख करोड़

रु पये की ऋण-स्वीकृति में से 32.40 लाख करोड़ रु पये के ऋण जारी किए जा चुके हैं। जाहिर है, इस योजना की निगरानी सभी स्तरों पर प्रभावी रूप में हो रही है।

इस मुद्रा योजना ने भारतीय बाजार के स्वरूप को भी बड़े सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसे एक आंकड़े से समझा जा सकता है। इस योजना के ‘शिशु’ श्रेणी में, जिसमें अधिकतम ऋण 5०० रु पये का दिया जाता है, उसमें 2015-16 में ऋण का औसत आकार मात्र 19411 रु पये था, जो बीते साल में लगभग दुगुना हो गया-37400 रुपये। इस मुद्रा योजना के तहत ‘शिशु’ श्रेणी में ही तीन चौथाई से अधिक ऋण दिए गए हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि बैंकों ने नये-नये उद्यमियों का स्वागत उद्यम-जगत में किया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भारतीय भूभाग के पूरे फैलाव को बड़े रोजक तरह से प्रभावित किया है। एक तरफ इसने पिछड़े राज्यों में नये उद्यमियों की पौध खड़ी की है, तो वहीं विकसित राज्यों में भी उद्यमियों का नये तरीके से वित्तपोषण किया है।

खास खबर...

महिला होमगार्ड के सैकड़ों पदों पर भर्ती परीक्षा 22 को

रायपुर। होमगार्ड विभाग द्वारा 1715 महिला नगर सैनिकों (छात्रावास ड्यूटी) तथा 500 नगर सैनिकों (जनरल ड्यूटी) के रिक्रूट पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 22 जून 2025 को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा राज्य के चार जिलों रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में संपादित होगी। होमगार्ड विभाग में 1715 महिला नगर सैनिकों (छात्रावास ड्यूटी) तथा 500 नगर सैनिकों (जनरल ड्यूटी) के रिक्रूट पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2024 में शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा चार संभागीय केंद्रों में रायपुर बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में आयोजित की गई थी। जिसमें पात्र 20,137 अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। चयनित सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम वेबसाइट लिंक में जाकर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी एवं जन्म तिथि डालकर अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पर लिखित परीक्षा हेतु आवेदन करेंगे। व्यापम द्वारा पंजीयन नंबर पर ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। जिन पात्र अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट में जाकर पंजीयन एवं आवेदन सबमिट नहीं किया जाएगा वे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से वंचित होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा होमगार्ड विभाग के वेबसाइट पर पूर्व में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किए जाने की अनुमति नहीं होगी। व्यापम की वेबसाइट पर आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा कार्यक्रम व्यापम वेबसाइट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 मई 2025 शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। परीक्षा तिथि 22 जून 2025, परीक्षा का समय पूर्वाह्न 2 बजे की होगी। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 13 जून 2025 को एवं परीक्षा केंद्र रायपुर, बिलासपुर जगदलपुर एवं अंबिकापुर में परीक्षा आयोजित होंगे।

भागवत कथा सुनकर भाव विमोह हुए श्रोता

कोरबा। वैष्णव निवास में बीते मंगलवार 8 अप्रैल से प्रारंभ श्रीमद्भागवत कथा महापुराण ज्ञानयज्ञ सप्ताह के दूसरे दिन कथावाचक नारायण महाराज ने वाराह अवतार, कपिलदेव जन्म और ध्रुव चरित्र के प्रसंगों का वर्णन किया और कथा सुनाई। जिसे सुन श्रोता भावविभोर हो गए।कथावाचक ने कथा में वाराह अवतार का वर्णन करते हुए बताया कि जब सनकादिक ऋषियों ने बैकुंठ धाम के द्वारपालों जय और विजय को तीन- तीन जन्म होने तक राक्षस होने का श्राप देकर भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु होकर उद्धार का उपाय बताया। सतयुग में भगवान ने हिरण्यशक और हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए वाराह और नरसिंह का अवतार लिया। त्रेता युग मे यही जय- विजय रावण और कुम्भकर्ण ननकर आए जो श्रीराम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। द्वापर युग मे कंस और शिशुपाल बने तो श्रीकृष्ण के हाथों इनका उद्धार हुआ। इस तरह तीन जन्मों के पश्चात जय- विजय पुनरु बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पाषांड के रूप में लौट आए। वहीं भगवान विष्णु के पांचवे अवतार कपिल मुनि के जन्म कथा का वर्णन करते हुए कहा कि कपिल मुनि विष्णु जी के 24 अवतारों में से प्रमुख अवतार है, जिन्हें अगिन का अवतार भी कहा गया है। कथा के अनुसार सतयुग में कदम ऋषि ने सरस्वती नदी के तट पर दस हजार वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान से ऐसी पत्नी का वरदान मांगा जो गृहस्थ जीवन और भक्ति मार्ग दोनों में साथ दें। भगवान के निर्देश पर उनका विवाह स्वायंभुव मनु की पुत्री देवहूति से हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन लिया। कपिल मुनि के साथ उनकी नौ बहने जो कला, अनुसूय्या, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति थी। कपिल मुनि ने सततान धर्म के संरक्षण के लिए अवतार लिया और सांख्य दर्शन तथा कपिल गीता जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना की, जिसमे जीवन जीने की कला का ज्ञान समाहित है। नारायण महाराज जी ने ध्रुव चरित्र के बारे में बताते हुए कहा कि एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव भी खेलते हुए राजमहल में पहुँच गए, उस समय उनकी अवस्था पांच वर्ष की थी। उत्तम राजा उत्तनपाद की गोद मे बैठा हुआ था।

विचार फॉर विकसित छत्तीसगढ़: सीएम साय ने युवाओं के साथ किया संवाद

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को नवा रायपुर में विचार फॉर विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं के साथ आत्मीय संवाद कर छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य और विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने युवाओं से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप प्रमोशन और उद्योगों से जुड़ाव जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और राज्य के समग्र विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अब अंतिम साँसें गिन रहा है और मार्च 2026 तक नक्सल का समूल नाश होगा।



छत्तीसगढ़ की यह सुंदर धरती विकास की नई ऊँचाइयों को छुपगी और शांत, सुरक्षित, खुशहाल और समृद्ध प्रदेश के रूप में इसे नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर में एएनआई द्वारा आयोजित विचार फॉर विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में

शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने एएनआई की संपादक श्रीमती स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट में अपने पारिवारिक, राजनीतिक जीवन और मुख्यमंत्री के रूप में अब तक के सफर और उपलब्धियों पर खुलकर बातचीत की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने प्रदेशवासियों के हित में मोदी की गारंटी की बात कही थी और हमारी सरकार ने बड़े निर्णय लेते हुए इसे पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश मोदी की गारंटी पूरी कर दी गई हैं। हमारी

सरकार ने पहले ही कैबिनेट में 18 लाख गरीब परिवारों को आवास मुहैया कराने का बड़ा फैसला लिया था। प्रदेश की माताओं-बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रतिमाह 71000 की राशि प्रदान की जा रही है। पीएएससी की परीक्षाओं में युवाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ सीबीआई जांच जैसे बड़े निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को गति देने के लिए निवेश अनुकूल नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। इस नीति की सफलता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि इसके लागू होने के बाद से सरकार को करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। हमारा उद्देश्य निवेश के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार देना भी है। श्री साय ने कहा कि हमने विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में हर प्रदेशवासी की अहम भूमिका होगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भागत, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।

स्वच्छ, सुंदर और विकसित कवर्धा की दिशा में प्रशासनिक पहल : नवीन बाजार होगा सुव्यवस्थित

श्रीकंचनपथ न्यूज

कवर्धा। स्वच्छ, सुंदर और विकसित कवर्धा की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज शनिवार सुबह कवर्धा नगर के सबसे बड़े नवीन बाजार का निरीक्षण किया और बाजार को सुव्यवस्थित करने हेतु अनेक निर्देश दिए।

एसडीएम श्री मुकेश रावटे, मुख् नगर पालिका अधिकारी श्री रोहित साहू, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि एक दिन पूर्व शुक्रवार को कलेक्टर गोपाल वर्मा एवं पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने नगर विकास के उद्देश्य से व्यापारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की थी। बैठक में व्यापारियों से शहर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए, जिनमें से कई महत्वपूर्ण सुझावों को गंभीरता से संज्ञान में लिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि कवर्धा हमारा शहर है और इसे सुंदर तथा स्वच्छ बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है तथा प्रमुख मार्गों की नालियों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि कोई भी सफाईकर्मी सड़क का कचरा नालियों में न डाले, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और अपने स्तर से योगदान दें।

पालिका अध्यक्ष ने मांगा जनसहयोग: नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने में व्यापारियों द्वारा दिए गए सुझाव अत्यंत उपयोगी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी सुझावों पर गंभीरता से अमल किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि नालियों पर कचरा न फेंके और नालियों के ऊपर बने अवैध चबूतरों को स्वयं हटाएं, ताकि समय पर साफ-सफाई संभव हो सके।

जनजाति समाज का गौरवमयी इतिहास रहा है : केदार कश्यप

श्रीकंचनपथ न्यूज

मोहला। प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप आज जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के ग्राम पंचायत टोला गांव ब्राह्मण भेड़ी में आयोजित प्रतिभावाण छात्र-छात्राओं एवं नवनिर्वाचित जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य एवं सरपंचों का सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

उन्होंने यहां आयोजित गरिमामयी कार्यक्रम से संबोधित करते हुए कहा कि जनजाति समाज का गौरवमयी इतिहास रहा है। जनजाति समाज के अनेकों विभूतियों ने देश और समाज को एक दिशा देने का उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज आदिकाल से पर्यावरण के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि



भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गैंग सिंह जैसे विभूतियों ने समाज को गौरवान्वित किया है। उन्होंने आगे कहा कि

जनजाति समाज विपरीत परिस्थिति में भी लड़ने की अदम्य साहस रखता है। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज के गौरवमयी इतिहास,

परंपरा, संस्कृति और विरासत को सहेजे रखने के लिए समाज के सभी नागरिकों की भागीदारी की जरूरत है।

मंत्री कश्यप ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार जनजाति समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूरे समाज को गौरवान्वित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी आज अनेक क्षेत्रों में अपना परचम लहराकर समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज को संगठित और एकजुटता के साथ रहकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर मंत्री कश्यप ने क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इसके

साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य एवं सरपंचों को प्रतीक चिन्ह भेंटकर कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कबड्डी खेल के विजेता खिलाड़ियों को भी प्रतीक चिन्ह भेंटकर कर सम्मानित किया। ग्राम वासियों की मांग पर कबड्डी खेल के लिए उपयोग में आने वाले मेट, सामुदायिक भवन, धान खरीदी केन्द्र खोलने सहित क्षेत्र के विकास को देखते हुए सभी आवश्यक कार्ययोजना को पूरा करने का भरोसा दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह, वनमण्डलाधिकारी दिनेश पटेल, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह, अपर कलेक्टर विजेन्द्र सिंह पाटले सहित अन्य अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिक संख्या में गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे।

आरना इंटरप्राइजेस

कांटावाला

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

इलेक्ट्रॉनिक तराजू एवं सीसीटीवी कैमरा के विक्रेता व सुधारक

सर्कुलर मार्केट केम्प-2, भिलाई, न्यु जेपी स्पोर्ट्स के सामने

7828844440, 9993045122

नया बस स्टैंड, शिव मंदिर रोड, दुर्ग, 09981370285, 9302833333

वाटरप्रूफ़ फायरके विक्रेता एवं सुधारक

आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता

अनुप ट्रेडर्स

सर्कुलर मार्केट, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई

प्रमोड इंटरप्राइजेस

गेंहू, चावल एवं दाल के थोक विक्रेता

लिंग रोड, केम्प-2, भिलाई-दुर्ग

फोन: 0788-2225449, 93290-13017

BIHAR BOOT HOUSE

Jawahar Market, Power House

Bhilai 9826181183



ब्रेस्ट इंप्लांट एक तरह की सर्जरी है जिसके जरिए ब्रेस्ट की शेप और साइज को ठीक किया जाता है या फिर बेहतर बनाया जाता है। इस सर्जरी में ब्रेस्ट के अंदर आर्टिफिशियल मेटेरिअल की एक परत लगाई जाती है। कई बार यह बात सामने आती है कि क्या ब्रेस्ट इंप्लांट के बाद शिशुओं को स्तनपान यानी ब्रेस्टफीडिंग कराया जा सकता है।

क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट के बाद ब्रेस्टफीडिंग संभव है?

जानकारों के मुताबिक सभी प्रकार के ब्रेस्ट इम्प्लांट से स्तनपान यानी ब्रेस्टफीडिंग में समस्या नहीं होती। आमतौर पर तीन तरह के ब्रेस्ट इम्प्लांट किये जाते हैं। इम्प्लांट की एकजीलरी तकनीक में बगल यानी आर्मपिट के नीचे चीरा लगाकर इम्प्लांट किया जाता है। आर्मपिट के आसपास की मांसपेशियां ब्रेस्ट और मिल्क से नहीं मिली होती, इसलिए ऐसे इम्प्लांट से ब्रेस्टफीडिंग पर कोई असर नहीं

पड़ता। इन्फ्रा-ममरी तकनीक में ब्रेस्ट के नीचे चीरा लगाया जाता है। एकजीलरी तकनीक की ही तरह यह भी सुरक्षित है, और ब्रेस्टफीडिंग के लिए बाधक नहीं होता। साथ ही स्तन से दूध भी आसानी से निकलता है। भारत में इम्प्लांट के लिए आमतौर पर यही दो तरीके अपनाए जाते हैं। इससे ब्रेस्टफीडिंग की समस्या नहीं होती, बल्कि इसके नतीजे भी अच्छे निकलते

हैं। इंप्लांट के बाद स्तन भी नेचुरल दिखते हैं और निशान भी नहीं पड़ते। पेरिआरिओलर तरीके से ब्रेस्ट इंप्लांट अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरीके का चुनाव नहीं करना चाहिए। इसमें निप्पल के पास चीरा लगाया जाता है। जिससे उन टिशु को नुकसान पहुंचता है जो ब्रेस्टफीडिंग के लिए जरूरी हैं। साथ ही इससे दूध निकलने का रास्ता बाधित हो जाता है।

गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए आजमाए ये तरीके



गर्मी के मौसम में हेल्थ को लेकर ज्यादा ही सावधान रहने की जरूरत होती है। इनदिनों बड़ी आसानी से आपकी तबियत खराब हो सकती है। इस आर्टिकल में हम आपको यह बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में आप अपनी सेहत को कैसे ठीक रख सकते हैं।

पानी

गर्मी के मौसम में इंसान के शरीर को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में सुबह उठने के साथ ही आपको भरपूर पानी पीना चाहिए। गर्मी के दिन में कोशिश करें की आप चाय का सेवन ना करें। इससे अपच बढ़ती है।

नारियल पानी

गर्मी के मौसम में आप रोज नारियल पानी पी सकते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। नारियल पानी आपके शरीर में गर्मी के दिनों में अमृत की तरह

काम करता है। नारियल पानी के साथ ही गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा दही का सेवन करना चाहिए। दही में कई तरह के एंटीबायोटिक होते हैं। दही से अपच दूर होती है और शरीर में ठंडक बनी रहती है।

फल

गर्मी में नाश्ते के वक्त फलों का सेवन करें। फल आपको ताजगी और फुर्ती देंगे। गर्मी से बचने के लिए फल रामबाण उपाय है। वहीं इस मौसम में चने का सेवन भी आपके शरीर को देगा ठंडक। चने के सेवन से ज्यादा धुप में रहने से भी पको अधिक प्यास नहीं लगती है।

धनिया, पुदीना और प्याज

खाना खाते समय गर्मी के मौसम में अपना पाचन ठीक रखने के लिए खाने के साथ धनिया, पुदीना और प्याज जरूर खाएं। इसकी चटनी बना कर खाने से गर्मी के दिन में आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं इस आसान तरीके से आप अपने पेट के तकलीफ से बचे हुए रहेंगे।

गर्मियों में इन घरेलू नुस्खों से दूर करे स्किन टैनिंग



तपती, झुलसती गर्मियों में त्वचा के कालापन से परेशान होकर ब्यूटी सैलून जाने के बजाय इस बार इन प्राकृतिक उपायों को अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकती हैं।

नींबू का रस:

प्रभावित स्थान पर नींबू का रस लगाएं। इसे 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। कुछ सप्ताह यह करने पर त्वचा का कालापन और दाग धब्बे भी कम होंगे। नींबू के रस के साथ खीरा या दही मिलाकर भी लगा सकते हैं।

दही:

त्वचा पर दही और अन्य दुग्ध उत्पाद लगाने से त्वचा मुलायम होती है और उसकी रंगत और दाग धब्बों में भी सुधार होता है।

एलोवेरा, गुलाब जल और ग्लीसरीन:

इन तीनों का मेल त्वचा की खूबसूरती के लिए बेहद प्रभावशाली है। यह दाग धब्बों और कालापन को हल्का करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है।

जई का आटा, शहद, दही:

धूप के कारण झुलसी त्वचा की मृत कोशिकाओं को दूर करने के लिए ये कारगर घरेलू स्क्रब हैं। त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने से कुछ दिनों में कालापन दूर हो जाता है और त्वचा खिली निखरी हो जाती है।



कमजोर हड्डियां, जोड़ों में दर्द आदि ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके लक्षण केवल बुढ़ापे या बचपने में देखे जाते थे। लेकिन अब इनके लक्षण युवाओं में भी देखे जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि तनाव के कारण हाइपरटेंशन, हृदय रोग, पाचन संबंधी विकार, अवसाद और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन अब इसका असर हड्डियों पर भी पड़ने लगा है। इसका आपकी हड्डियों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

आपकी हड्डियों को कमजोर बना सकता है तनाव!

तनाव के कारण कुछ युवाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या देखी गई है। शहरी महिलाओं में काम और परिवार की देखभाल के चलते ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। नींद की कमी, कम फिजिकल एक्टिविटी और घंटों काम करना आदि से तनाव पैदा होता है। आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए प्राकृतिक उपचार का उपयोग कर सकते हैं।

जब तनाव कम होता है, तो उसे सामान्य माना जाता है। लेकिन तनाव ज्यादा होने पर इसका बॉडी और माइंड पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पहला, जब तनाव ज्यादा होता है, तो बॉडी

कोर्टिसोल हार्मोन जारी करती है। बॉडी द्वारा कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ने से हड्डी के निर्माण में बाधा होती है। वास्तव में बॉडी कोर्टिसोल के पीएच संतुलन को प्रभावहीन

करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम जारी करती है। दूसरा, तनाव ज्यादा होने पर व्यक्ति अपनी स्वस्थ आदतें जैसी पूरी नींद, पर्याप्त भोजन और एक्सरसाइज करना आदि छोड़ देता है। इन सबके कारण भी हड्डी की हानि हो सकती है।

डॉक्टर के अनुसार, अपने डॉक्टर की सलाह के बाद आप कैल्शियम से भरपूर फूड्स और सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर सकते हैं। शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों का ख्याल रखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इससे बचने के लिए शारीरिक गतिविधि बनी बहुत जरूरी है। आप योग और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। 35 साल की उम्र के बाद अपने हड्डी घनत्व की जांच कराएं।

बड़े काम का जामुन, भूख बढ़ाता है

जामुन स्वाद में खट्टा-मीठा होने के साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। जामुन खाने से भूख भी बढ़ती है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। यह गर्मी की शुरुआत में ही बाजार में आने लगता है। इसमें ऐंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। यह पाचन तंत्र के लिए भी काफी फायदेमंद है। बस एक बात का ध्यान रखें कि खाली पेट जामुन न खाएं। जामुन के फायदों पर एक नजर



- मुंहसे होने पर जामुन की गुठलियों को सुखाकर पीस लीजिए। रात को सोते समय इस पाउडर में गाय का दूध मिलाकर चेहरे पर लगाइए, इस लेप को सुबह ठंडे पानी से धो लीजिए।
- विटमिन सी की कमी को दूर करने के लिए जामुन खाना अच्छा रहता है। बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि जामुन में विटमिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है।
- जामुन का सिरका बनाकर बराबर मात्रा में पानी मिलाकर खाने से न केवल भूख बढ़ती है, बल्कि कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है।
- जामुन में फ्लेवोनॉइड्स, फेनॉल्स, प्रोटीन और कैल्शियम भी पाया जाता है,

- जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
- ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में मिलने वाली शुगर शरीर को हाइड्रेट करने के साथ ही कूल और रिफ्रेश करती है।
- अगर आपको कमजोरी महसूस होती है या आप अनीमिया से पीड़ित हैं तो जामुन खाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
- अगर आपको ऐसिडिटी की समस्या रहती है तो काले नमक में भुना जीरा मिलाकर पीस लें। फिर इसके साथ जामुन खाएं। ऐसिडिटी की समस्या दूर हो जाएगी।
- अगर आपका बच्चा बिस्तर गीला करता है तो जामुन के बीजों को पीसकर आधा-आधा चम्मच दिन में दो बार पानी के साथ पिलाएं।
- गले के रोगों में जामुन की छल को बारीक पीस लें। इसको पानी में घोलकर 'माउथ वाश' की तरह गरारा करें। इससे गला तो साफ होगा ही, सांस की दुर्गंध भी दूर हो जाएगी और मसूढ़ों की बीमारी भी दूर हो जाएगी।
- विषैले कीड़ों के काटने पर जामुन की पत्तियों का रस पिलाना चाहिए। काटे गए स्थान पर इसकी ताजी पत्तियों का पुट्रिस बांधने से घाव ठीक होने लगता है क्योंकि जामुन के चिकने पत्तों में नमी सोखने की क्षमता होती है।

बदहजमी ठीक करने में कारगर है पुदीना

पुदीना का इस्तेमाल न सिर्फ औषधि के रूप में किया जाता है वरन् खाने में फ्लेवर लाने के लिए भी किया जाता है। प्राचीन काल से पुदीना बदहजमी संबंधी किसी भी समस्या के उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

शायद आप सोच रहे होंगे कि पुदीने में ऐसा क्या है जो हाजमा को बेहतर बनाने में इतना मदद करता है। पुदिना में फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सिडेंट होता है जो खाना को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। इस हर्ब में मेन्थॉल रहता है जो

डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बाइल सॉल्ट और एसिड के निष्कासन को एक्टिव करता है। बदहजमी के कारण पेट में जो गैस बनने लगता है उसको ये पेट के मांसपेशियों को शांत करके निकालने में पुरी तरह से सहायता करता है। मेन्थॉल के कारण जो मांसपेशियों का संचालन अच्छी तरह से होने के कारण बदहजमी के लक्षणों के दूर करके बैचनी में चैन दिलाता है। पुदीना बदहजमी के कारण पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी जैसे लक्षणों से मिनटों में आराम दिलाता है।



एक दुसरे की संस्कृति को समझेंगे और सम्मान करेंगे तभी सशक्त भारत का निर्माण होगा - राज्यपाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजभवन में अरूणाचल प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा राज्यों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि जब हम एक-दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, स्वीकार करेंगे और उसका सम्मान करेंगे तभी सशक्त भारत का निर्माण होगा।

केन्द्र सरकार के एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत यह आयोजन किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले इन राज्यों के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। राज्यपाल ने स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर शुरू किए गए 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम हमें आपसी सांस्कृतिक आदान-प्रदान आर्थिक सहयोग और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की विविधता यहां के खान-पान, पहनावे, परंपराओं, रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों में देखी जा सकती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं की विविधता देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि 'राजाओं की भूमि' के रूप में जाना जानेवाला राजस्थान अपने शाही इतिहास, भव्य किलों और महलों के साथ भारतीय वीरता और सांस्कृतिक गौरव की कहानियों को संरक्षित किए हुए है। इस राज्य के लोग बहुत मेहनती होते



हैं। यहां के लोग अपनी मेहनत और लगन के बल पर आर्थिक उन्नति कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों में वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में मारवाड़ी समाज ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। राजस्थान के लोग जहां भी जाते हैं वहां की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग का एक अदभुत नमूना है, भारत में ऐसा कहीं नहीं है।

राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़िया और उड्डिया भाई-भाई हैं। दोनों राज्यों की संस्कृति एक-दूसरे से बहुत मिलती-जुलती है। छत्तीसगढ़ में 35 लाख ओडिया भाई रहते हैं। ओडिशा राज्य के नागरिक विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और खनन में अपनी विशेषज्ञता के साथ छत्तीसगढ़ आए हैं। उनके कृषि ज्ञान और

कला केन्द्र के कलाकारों को राज्यपाल ने दिया स्वेच्छानुदान राशि

कार्यक्रम में कला केंद्र रायपुर के वायलिन वादक बच्चों आरिव झा और अमेय शर्मा ने वायलिन पर राग बैरागी भैरव की प्रस्तुति की। राज्यपाल ने उनकी प्रस्तुति की सराहना की और इन बच्चों सहित अन्य वायलिन वादक बच्चों धनंजय साहू और देवव्रत कहार, प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये की राशि तथा कला केंद्र रायपुर संस्था को दस हजार रुपये की राशि अपने स्वेच्छानुदान मद से प्रदान की। कार्यक्रम में राज्यपाल के विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पाण्डेय, उप सचिव हिना अनिमेष नेताम, इन सभी राज्यों के छत्तीसगढ़ में निवासरत, बच्चे, युवा, महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कौशल ने छत्तीसगढ़ की मदद की, जबकि खनन में उनके अनुभव ने राज्य में खनन उद्योग के विकास में मदद की। इसके अलावा, ओडिशा के नागरिकों ने अपने अनूठे त्योहारों, नृत्य रूपों और हस्तशिल्प से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध किया है।

श्री डेका ने अरूणाचल प्रदेश की विशेषताओं का जिक्र किया और कहा कि अरूणाचल प्रदेश की संस्कृति विशिष्ट है क्योंकि इसमें 26 विभिन्न जनजातियाँ सहित 100 से अधिक उप जातियों की



कला केन्द्र के कलाकारों को राज्यपाल ने दिया स्वेच्छानुदान राशि

अपनी-अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करती। यहां हिन्दू, बौद्ध, ईसाई समुदाय के लोग भी मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने कहा कि अरूणाचल प्रदेश को पारंपरिक शिल्प कौशल का उपहार प्राप्त है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित इन राज्यों के बच्चों एवं युवाओं ने अपने राज्य की संस्कृति एवं लोक परंपरा आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। ओडिया नृत्य, घूमर एवं

अन्य राजस्थानी लोक नृत्य सहित अरूणाचल प्रदेश के जीवंत नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया।

ओडिशा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित विधायक पुरंदर मिश्रा, राजस्थान के प्रतिनिधि महेन्द्र धाड़ोवाल और अरूणाचल प्रदेश की प्रतिनिधि क्लार्क कु ने राज्यपाल को अपने राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल द्वारा भी राजकीय गमछा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

सुशासन तिहार के पहले चरण में जिले में एक लाख से अधिक आवेदन मिले

श्रीकंचनपथ न्यूज

धमतरी। सुशासन तिहार से लोगों की समस्याओं, मांग और शिकायतों का समाधान हो रहा है। सुशासन तिहार को लेकर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है व ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग आवेदन लेकर उत्साहपूर्वक जमा किए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में भी लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आशान्वित हैं और उत्साह पूर्वक निगम क्षेत्र में रखी गई समाधान पेटियों में अपने आवेदन डाले हैं।

वहीं राजीव नगर हटकेश्वर वार्ड निवासी सुलेखा अली ने बताया कि वह 80ब दिव्यांग और विधवा महिला है। उन्होंने बताया कि वह प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन देने आई हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं को रखने का सरकार ने मौका दिया है। आम जनता अपनी मांगों को अब सीधे सरकार के समक्ष रख सकती है।

दानीटोला वार्ड की श्रीमती वंदना साहू ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना के तहत सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने वाली राशि उन्हें अब तक अप्राप्त है। उन्होंने साय सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें उक्त राशि प्रदान करने में सहयोग प्रदान करें, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

समाधान शिविरो की सार्थकता को बताते हुए नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने कहा कि 8 अप्रैल से शुरू सुशासन तिहार में

जिले के सभी नगरीय निकायों में लगभग 12 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं जिले की जनपद पंचायतों में एक लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। गौरतलब है कि सुशासन तिहार 2025 का आयोजन तीन चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए गए हैं। अब दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरी एवं अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

समाधान शिविरो की सार्थकता को बताते हुए नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने कहा कि 8 अप्रैल से शुरू सुशासन तिहार में

को सब्जी बीज वितरण किया और मछली पालन विभाग ने 2 हितग्राहियों को मछली जाल और आईस बाक्स वितरण किया। ग्रामवासियों ने ग्राम करडेगा महाविद्यालय खेलने के लिए बजट स्वीकृत होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को दिया धन्यवाद ग्रामवासियों ने कहा कि अब करडेगा के आस पास के बच्चों को दूर पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जुदेवे ने सुशासन शिविर को सम्बोधित करते हुए जल संरक्षण और संवर्धन के लिए पानी बचाने की अपील की उन्होंने कहा कि जल है तो कल हम सबको आने वाले समय के लिए जल संग्रहण करना जरूरी है। उन्होंने शासन की सभी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर दुलदुला के जनपद पंचायत अध्यक्ष राजकुमार सिंह, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रविन्द्र गुप्ता ग्राम पंचायत करडेगा सरपंच श्रीमती आशा पैकरा एसडीएम

कुनकुरी नन्द जी पांडे; जनपद पंचायत सीईओ धनेश टेंगवार; जनप्रतिनिधिगण; जिला स्तरीय अधिकारी और ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कलेक्टर ने ग्रामवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिविर का उद्देश्य ग्रामवासियों के सामने ही उनकी समस्याओं का समाधान करना है। ताकि उन्हें जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता न पड़े उन्होंने कहा कि आज दिव्यांग शिविर का भी आयोजन किया गया है। जिसमें दिव्यांग जनों को बैदरी चलित ट्राईसाईकिल; श्रवण यंत्र; बैसाखी; छड़ी दिया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी आवेदन फवती; नामांतरण और राजस्व संबंधी आवेदन का निराकरण किया गया। सुशासन शिविर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल के महत्व के प्रति जागरूक करना है। जल हमारे जीवन के लिए अनिवार्य घटक है।

मौसम में बदलाव: आंखों में जलन, खुजली व सूजन जैसी होने लगी शिकायतें

कोरबा। तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों को आंखों से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा में फ्लिहाल ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं कि लोगों को आंखों से संबंधित समस्या है। ऐसे लोग कम खर्च पर उपचार करने स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में हैं और अगर उनकी जेब मजबूत है तो वह निजी क्लीनिक भी पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण आंखों में जलन, खुजली और सूजन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। नेत्र विशेषज्ञ ने बताया कि धूल और प्रदूषण भी इन समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें।

Jaquar Roca **Parryware** **AAJAY FLOWLINE**

Shri Vijay Enterprises

Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.

Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

जनजातीय कल्याण की योजनाओं के लक्ष्य को तेजी से पूरा करें: सोनमणि बोरा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। आदिम जाति विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि राज्य में जनजातीय कल्याण की योजनाओं को तेजी के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि बारिश के पहले सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया जाए। श्री बोरा ने कहा कि आगामी मानसून सीजन में राज्य में संचालित 3357 आश्रम छावनाओं, 15 प्रयास विद्यालयों एवं 75 एकलव्य विद्यालयों में 10 लाख पौधे लगाये जाएंगे। इसकी भी कार्य योजना पहले से तैयार कर ली जाए। प्रमुख सचिव श्री बोरा नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित विभागीय बैठक सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिले के सहायक आयुक्त सहित संबंधित अधिकारी जुड़े थे। श्री बोरा जनजातीय जीवनशैली पर आधारित निर्माणाधीन संग्रहालय का निरीक्षण भी किया।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ पीएम जनमन योजना, धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की निर्धारित लक्ष्यों को योजनाबद्ध तरीके से समय-सीमा में पूर्ण



किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत अति पिछड़े जनजातीय वर्ग के लोगों तथा उस गांव को शत-प्रतिशत व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाए। श्री बोरा ने योजना के तहत पक्का आवास, एग्रीक रोड, आंगनवाड़ी निर्माण, मोबाइल मेडिकल यूनिट, मल्टीपरपज सेंटर, विद्युत कनेक्शन, वनधन विकास केन्द्र सहित संचालित सभी गतिविधियों को विस्तार से जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि पक्के आवास सहित अन्य लक्ष्यों को 30 अक्टूबर 2025 से पहले हासिल कर लिया जाए। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को बारीश से पहले पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा

कि सहायक आयुक्त और नोडल अधिकारी निर्माण कार्यों का मॉनिटरिंग करें, ताकि सभी कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में संपन्न हो सकें।

उन्होंने सहायक आयुक्तों को जिले में कम से कम पांच गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए। प्रथम चरण में धमतरी, जशपुर, गरियाबंद एवं नारायणपुर जिले के सहायक आयुक्तों को इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी हितग्राहियों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पीएम जनधन खाता, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम मातृ वंदन योजना, जाति

प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पट्टा, स्वच्छ जल एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं शीघ्र पहुंचाई जाएं।

बैठक में आयुक्त पदुम सिंह एल्मा ने कहा कि छात्रावास-आश्रमों में साफ-सफाई, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ शौचालय, पढ़ाई की उचित व्यवस्था सहित सभी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। प्रमुख सचिव बोरा आगामी 15 एवं 16 अप्रैल को प्रदेश स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा करेंगे। दूसरे दिन 16 अप्रैल को रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में पदस्थ सहायक आयुक्तों की बैठक आयोजित की जाएगी।

उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्य सराहनीय : अरुण साव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा विधि एवं विधायी कार्य मंत्री अरुण साव छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा आयोजित उपभोक्ता जागरूकता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित सम्मेलन में आयोजित द्विदिनिक प्रतिवेदन के मुद्रित एवं ई-संस्करण का विमोचन भी किया। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा और सचिव अन्बलनगन पी. विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उपभोक्ता जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने, धोखाधड़ी व ठगी से बचाने तथा जागरूक करने में राज्य एवं जिला स्तरीय



उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सराहनीय कार्य कर रहा है। उपभोक्ताओं को ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधाएं भी मिल रही हैं। उनकी सहूलियत के लिए आयोग ऑनलाइन सुनुवाई प्रारंभ करने की भी तैयारी कर रही है। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद विधि के छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराने का काम करें। श्री साव ने आयोग के कार्यों को

मजबूती प्रदान करने और विस्तारित करने राज्य शासन से हर तरह का सहयोग प्रदान करने की बात कही। उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने व्यापक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम संचालित करने की घोषणा की।

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरडिया ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन की ओर से आयोग को भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे सभी

प्रस्तावों को सरकार ने स्वीकृत किया है। वर्तमान में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में ई-सुनुवाई की व्यवस्था है। आगामी तीन महीनों में हम इस व्यवस्था को प्रदेश के सभी 17 जिला स्तरीय आयोगों में लागू करने जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय मिले, इसके लिए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के साथ ही सभी जिला स्तरीय आयोग सक्रियता से काम कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति श्री चौरडिया ने कहा कि पिछले दो वर्षों में लोगों को न्याय दिलाने आयोग ने मामलों की तेजी से सुनुवाई की है। दो वर्ष पहले पूरे प्रदेश में दस हजार 600 मामले लंबित थे, जो अब घटकर 6500 रह गए हैं। अगले छह महीनों में सभी लंबित प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि आयोग आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए केस फाइलिंग, सुनुवाई और दस्तावेजीकरण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू करने जा रहा है। उन्होंने रायपुर में ज्यादा प्रकरणों को देखते हुए आयोग को एक अतिरिक्त बेंच प्रारंभ करने की भी जानकारी दी।

उपभोक्ता जागरूकता सम्मेलन को

संबोधित करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने कहा कि राज्य व जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के संचालन के लिए समुचित व्यवस्थाएं प्रदान करना राज्य शासन का दायित्व है। आयोग द्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए ई-फाइलिंग और ई-सुनुवाई की सुविधा विकसित की जा रही है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए राज्य शासन और आयोग मिलकर काम करते रहेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अन्बलनगन पी. ने अपने संबोधन में कहा कि विगत 25-30 वर्षों में बाजार में हर सामग्री की वेराइटी काफी बढ़ी है। उत्पादों और उत्पादकों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच उपभोक्ता हितों के संरक्षण की जरूरत भी बढ़ रही है। उपभोक्ताओं को जागरूक व शिक्षित करने तथा न्याय दिलाने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। राज्य शासन और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की पूरी कोशिश है कि सभी नागरिकों तक इसका लाभ पहुंचे।

CAR DECOR

House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories

Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai

Mo.9300771925, 0788-4030919

K. Satyanarayan

SAIRAM

Mobile Accessories

मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़कों की आवश्यकता है

7000415602

Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES

FURNITURE PALACE

Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture

Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स

आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता

बेन्टक्स एवं प्रहाल उपलब्ध यहां उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है

मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई

9827938211, 9827171332

Ashok JEWELLERY

Gifts • Toys • Cosmetics Perfumes • Sia Jewellery

Beside Parakh Jewellers, Akash Ganga, Supela, Bhilai

Hello: 0788-4052727

Mukesh Jain 9009959111 Rishabh Jain 8103831329

खास खबर

आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी, दो सटोरिये गिरफ्तार

कवर्धा । कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट मैचों में सट्टा संचालन करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है वहीं मामले में दो अन्य के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। बता दें कि आईपीएल सत्र के साथ ही सट्टेबाजी गतिविधियों में अचानक तेजी आने लगी थी, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा पहले ही जिले में सट्टा कारोबारियों पर निगरानी बढ़ाने और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए थे। इसी क्रम में थाना कवर्धा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 11.04.2025 की रात मुखबिर सूचना के आधार पर उप निरीक्षक रजनीकांत दीवान द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा खेलते-खिलाते दो आरोपियों को रंगे हाथ पकड़कर उनके पास से दो एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन में एसडीओपी कवर्धा कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में की गई इस कार्रवाई में यह बात सामने आई कि दोनों आरोपी ऑनपैनलडॉटकॉम नामक वेबसाइट पर अपनी-अपनी आईडी के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेल-खिला रहे थे। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने पृष्ठताछ में यह स्वीकार किया कि वे आईडी से सट्टा लगाकर पैसा कमाने का काम करते हैं, और उनके मोबाइल में इस संदर्भ में आवश्यक रिकॉर्ड भी मिला है। मामले में पुलिस ने गोपी गुप्ता पिता कृष्णा गुप्ता, उम्र 42 वर्ष, निवासी वाई क्र. 12 बुद्ध महादेव मंदिर के पास, कवर्धा तथा आशीष गुप्ता पिता स्व. राममकर गुप्ता, उम्र 35 वर्ष, निवासी गुप्ता पारा, कवर्धा को गिरफ्तार कर दोनों के विरुद्ध धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

ट्रेलर पलटने से सड़क पर बिखर गया राखड़-वाहन चालक घायल

कोरबा । दर्रा से राखड़ लेकर पाली की ओर आ रही ट्रेलर पाली के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग के ग्राम पाली-कोसाबाड़ी के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। उक्त घटना में वाहन चालक घायल हो गया। उसे राहगीरों की मदद से पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वाहन के पलटने से इसमें लोड राखड़ सड़क पर बिखर गया। लोगों ने बताया कि वाहन चालक का नियंत्रण अचानक खो गया इससे यह हादसा हुआ। उल्लेखनीय हैं की कोरबा में विभिन्न कंपनियों का राखड़ बांध स्थित है। यहां से रोजाना भारी मात्रा में राखड़ को ट्रेलर या हाइवर पर लोड कर अलग-अलग दिशाओं में भेजा जा रहा है। इस कार्य में कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां शामिल हैं, जो भाड़े पर गाड़ी लेकर राखड़ का परिवहन कर रही है, लेकिन आरोप हैं की तय मापदंडों के अनुसार राखड़ का परिवहन नहीं हो रहा है। इससे लोगों के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो गई है।

रायपुर में 3 लाख भेजकर स्वास्थ्यकर्मों से 33 लाख टगो: शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफे का दिया लालच

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर में शातिर टग ने करीब 2 लाख 75 हजार रुपए भेजकर 33 लाख की टगी की है। सरकारी कर्मचारी और उसकी पत्नी को शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का लालच देकर फंसाया था। मुनाफे के भेजे पैसे भी केरल में किए गए फ्रेंड के हैं, इसलिए केरल पुलिस ने पीड़ित के अकाउंट को फ्रिज कर दिया। अब पीड़ित स्वास्थ्यकर्मों अपने अकाउंट को अन-फ्रीज कराने के लिए भटक रहा है। उसने मोवा पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें अपने साथ टगी की वारदात के बारे में बताया है।

जानिए कैसे हुआ फ्रॉड

मोवा थाना प्रभारी कमलेश देवांगन ने बताया कि दलदल सिवनी निवासी मनोज कुमार स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। वॉट्सऐप नंबर पर टग ने खुद को SBI Securities और IBHK (IBHKR Zxx-Origin Capital Increase Plan) का एजेंट बताकर संपर्क किया। उन्हें एक वॉट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया, जिसमें पहले से कई लोग शामिल थे। रुप में शेयर मार्केट में मुनाफे की गारंटी देने का दावा किया गया, जिसके बाद झांसे में आकर उन्होंने 7 अक्टूबर 2024 को अपनी पत्नी के एचडीएफसी खाते से यूको बैंक के एक खाते में 2 लाख रुपए



ट्रांसफर किए।

अलग-अलग खातों से 32.80 लाख ट्रांसफर

इसके तीन दिन बाद 2.75 लाख रुपए मुनाफे के रूप में वापस आए, जिससे उन्हें भरोसा हो गया। इसके बाद स्वास्थ्यकर्मों ने 3 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच अलग-अलग खातों में 32 लाख 80 हजार रुपए ट्रांसफर कर



दिए। इन ट्रांजेक्शन में बंधन बैंक, यूको बैंक, ICCIC, HDFC और रोहताश इलेक्ट्रिसिटी जैसे खातों में रकम भेजी गई। इस दौरान कुछ राशि उनके HUF खाते से भी भेजी गई। इसके बाद जब उनके खातों में कोई लेनदेन नहीं हुआ और बैंक से जानकारी ली गई, तो पता चला कि उनके खाते में 2.75 लाख रुपए एक फ्रेंड खाते से आए थे। जिस कारण उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिया गया है। मनोज के बैंक अकाउंट में जो रुपए आए

लंदन का वीजा बनवाने के बहाने टगी

रायपुर। रायपुर में 6 लोगों से नौकरी के लिए लंदन का वीजा बनवाने के बहाने टगी की गई है। एक होटल के कुक ने कर्मचारियों से करीब 19 लाख रुपए ऐंट लिए। फिर होटल का काम छोड़कर भाग गया। कर्मचारियों ने जब फ़ोन से संपर्क किया तो उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। इस मामले में तेलीबांधा पुलिस शिकायत मिलने के बाद जांच में जुट गई है। तेलीबांधा पुलिस को समीर भीलवार ने बताया कि, मई 2023 में वह गौरव गार्डन तेलीबांधा में काम करता था। इस दौरान वहां पर सेफ(कुक) विवेक सिंह ठाकुर ने बताया कि विदेश में भी काम कर चुका है। लंदन में बहुत पैसा है हम सभी को मिलकर वहां जाकर कमाना चाहिए। विवेक ने कई दिनों तक इस बात को बोलते हुए अन्य कर्मचारियों को भी झांसे में ले लिया। इस दौरान गौरव गार्डन में काम करने वाले समीर भीलवार, अंकित रतोड़ी, छतलाल देवांगन, सुमीत मुसान, मनोज नाहक और मनीष एम संगमा ने कहा कि, उनके पास वीजा बनवाने के लिए पैसे नहीं है। तो विवेक सिंह ने कहा कि हर आदमी को साढ़े 3 लाख रुपए लगेंगे। पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है धीरे-धीरे करके दे दीजिएगा।

बड़ी मां की करतूत, बहन की बेटी का करा रही थी दुष्कर्म

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला अपनी छोटी बहन की बेटी का युवक से दुष्कर्म करा रही थी। नाबालिग अपनी बड़ी मां के घर रहने गई तो उसने एक युवक से परिचय कराया और कह दिया कि इसी से शादी करनी है। इसके बाद युवक बार बार घर आता और नाबालिग से जबरदस्ती करता। एक दिन वहां से निकलकर युवती अपनी मौसी के पास पहुंची और सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज किया और आरोपी युवक व पीड़िता की बड़ी मां गिरफ्तार कर लिया।

मिली जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल 2025 थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम की प्राथिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिक भतीजी 7 अप्रैल 25 को उसके घर आई थी। आने के बाद वह गुमसुम रहती थी। प्राथिया के द्वारा गुमसुम रहने का कारण पूछने पर, उसकी



नाबालिक भतीजी पीड़िता ने बताया कि एक राहुल नाम के लड़के के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। प्राथिया के द्वारा जब अपनी नाबालिक भतीजी पीड़िता से पूरी बात पूछने पर नाबालिक पीड़िता ने बताया कि तीन से चार माह पहले उसकी बड़ी मां ने एक राहुल नाम के लड़के को घर बुलाया था, जिससे नाबालिक पीड़िता का परिचय कराते हुए, उसकी बड़ी मां ने कहा था कि राहुल एक अच्छा लड़का है, इसी से तुम्हारी शादी करना है।

नाबालिक पीड़िता की बड़ी मां आरोपी राहुल को बार बार फ़ोन कर घर बुलाती थी, इसी दौरान 24 दिसंबर 2024 को रात्रि लगभग 11 बजे

नाबालिक अपने कमरे में सोई हुई थी व उसकी बड़ी मां बगल के कमरे में सोई हुई थी। अचानक आरोपी राहुल नाबालिक के कमरे में आया और उसके मना करने के बावजूद जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर भी, बगल के कमरे में सो रही उसकी बड़ी मां नहीं आई। सुबह नाबालिक पीड़िता के द्वारा घटना के संबंध में अपनी बड़ी मां को बताने पर, उसकी बड़ी मां ने आरोपी राहुल से तुम्हारी शादी कर दोगे, कहकर घटना के संबंध में किसी को भी बताने से मना कर दी। इसके बाद से आरोपी राहुल बार बार नाबालिक पीड़िता के घर आता था व नाबालिक पीड़िता का जबरन

दुष्कर्म करता था, इस कार्य में नाबालिक पीड़िता की बड़ी मां का भी आरोपी राहुल को समर्थन प्राप्त था।

रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली जशपुर में बीएनएस की धारा 64(2)(M),65(1) व 4,6,17 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी राहुल अनुबंधित ट्रांसपोर्ट रोड स्टॉल करने वाली पीड़िता की बड़ी मां को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की पृष्ठताछ में आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने व उनके विरुद्ध प्रयास अपराध सबूत पाए जाने से दोनों न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक अशा तिकी, सहायक उप निरीक्षक सोहलता सिंह, सहायक उप निरीक्षक विपिन किशोर केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक रीना प्रधान, आरक्षक परदेसी राम, महिला यादव आरक्षक मुनी देवी, अरुणा की सराहनीय भूमिका रही है।

करोड़ों रुपये गबन करने वाला फरार आरोपी फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार

रायपुर। दिनांक 18.09.2024 को प्राथी संतोष कुमार राय (फैक्ट्री मैनेजर अपोलो रिंगमी सिमगा + अपोलो बेंदरी उरला) द्वारा लिखित शिकायत आवेदन मे थाना उपस्थित हो कर रिपोर्ट दर्ज करवाया कि उनके फैक्ट्री द्वारा रॉ मटेरियल काईल जो टाटा स्टील एवं अन्य फर्मों से रेल के माध्यम से सिलयारी स्थित मलौद साईडिंग मे आने के बाद कंपनी द्वारा अनुबंधित ट्रांसपोर्ट रोड स्टार फ्लिट्स के द्वारा ट्रेलर के माध्यम से परिवहन कर अपोलो फैक्ट्री पहुंचाने का अनुबंध किया था. परन्तु ट्रांसपोर्टों द्वारा मार्च 2023 से जुलाई 2024 के बिच कुल 76 क्राईल जुमला कीमती 10 करोड़ को नहीं पहुंचा कर अमानत मे खयानत किया है कि रिपोर्ट पर धारा सदर मे अपराध क्रमाक

511/24 धारा 316(3),3(5) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना के प्राथी द्वारा दिनांक 03.04.2025 को चौकी उपस्थित आकर उरला बेन्द्री स्थित एपीएल अपोलो फैक्ट्री की 06 क्राईले कीमती लगभग 1 करोड़ भी उक्त आरोपीयो द्वारा उसी घटना स्थल से उसी तरीके से अमानत मे खयानत करने पर शिकायत पेश कर बयान दर्ज कराया जिसको विधिवत अपराध सदर मे संलग्न किया गया है। दौरान विवेचना के प्रकरण के अभियुक्त के पता तलाश उनके कार्यालय रायपुर मे किया गया जो कार्यालय मे उपस्थित नही मिले! प्रकरण के अभियुको के पता तलाश हेतु मुल पतों मे तलाशी हेतु पुलिस टीम रवाना किया गया।

छत्तीसगढ़ में गोवंश से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, तस्क़र गिरफ्तार, पत्थलगांव के रास्ते झारखंड जाने की थी तैयारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने गाँवों से भरी ट्रक को पकड़ने में सफलता पाई है। तस्क़र ट्रक के साथ गाँवों को झारखंड की ओर ले जा रहा था। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 40 जीवित गोवंश व 7 मृत गोवंश बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके अन्य साथियों की तलाशी की जा रही है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर सभी जीवित गोवंश को सुरक्षित रखवाया। वहीं आरोपी के खिलाफ छ.ग. कृषक पशु परि. अधि. की धारा 4, 6, 10 के तहत कार्रवाई की गई है। मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र का है।

दरअसल एसपी शशि मोहन को बीती रात मुखबिर से सूचना मिली कि पत्थलगांव की ओर से कांसाबेल, कुनकुरी होते हुये झारखंड की ओर एक ट्रक सीजी 14 एमडी 1376 में मवेशियों की कस्तूतापूर्वक भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना पर थाना कांसाबेल, चौकी दोकड़ा एवं थाना कुनकुरी से पुलिस टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। टीम को उक्त ट्रक के



कांसाबेल से त्रास होने की जानकारी मिलने पर कुनकुरी में निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व में तगड़ा बेरिकेड लगाकर नाकाबंदी की गई। पुलिस के भारी दबाव में आकर उक्त ट्रक का चालक कुनकुरी के नेशनल हाईवे में वाहन को खड़ी कर

भाग रहा था, जिसे पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर पकड़ा। ट्रक को जब्त कर थाने लाया गया।

पृष्ठताछ में आरोपी ने अपना नाम मो. सरफ़ाज़ शाह बताया। आरोपी ने बताया कि एक दिन पहले शुक्रवार की सुबह अपने अन्य साथियों

के साथ मवेशी लेने बिलासपुर गया था। ट्रक को उसका साथी चला रहा था। बिलासपुर से लगभग 15 किलोमीटर पहले एक गांव में रोड किनारे ट्रक को खड़ी किया। उसका साथी पहले से गौ-वंश को बंधवाकर रखा था, फिर ये सभी मिलकर

के साथ मवेशी लेने बिलासपुर गया था। ट्रक को उसका साथी चला रहा था। बिलासपुर से लगभग 15 किलोमीटर पहले एक गांव में रोड किनारे ट्रक को खड़ी किया। उसका साथी पहले से गौ-वंश को बंधवाकर रखा था, फिर ये सभी मिलकर

भिलाई की सबसे बड़ी चुड़ी की दुकान

निखार बैंगल

मो.- 9826186026

Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

भारतीय बैग हाउस

फैंसी स्ट्राली, स्कूल बैग, ऑफिस बैग, सफर बैग, लेपटॉप बैग, फैंसी छतरी, रेनकोट इत्यादि के विक्रेता

कृष्णा टाकीज रोड, बैंक ऑफ बडोदा के बाजू में रिसाली भिलाई, संजय गुप्ता: 93003-77572

राकेश ट्रेडर्स

राकेश ट्रेडर्स जो सर्व के पास था वह आगे चला गया है पिछले दस वर्षों से

Dealers

Marbles, Grinight, Black Stone, Nano & Double Charge Verified Tiles Digital Wall & Floor Tiles Cement Colour etc.

रायपुर १२२ पर माल उपलब्ध | 9302443750, 9907127357

Krishna Talkies Road, Beside Swami Aatmanad School, Risali, Bhilai - 490006

भिलाई मसाला उद्योग

शुद्ध कुटे हुए मसाले, पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि

128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्री टिकट सुविधा केंद्र

अधिसूचना क्र.: 2025/C/Chg./YTS/KMR दिनांक: 08.04.2025

भारत के राष्ट्रपति के ओर से वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर द्वारा रायपुर मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न स्टेशनों / स्थानों पर आरक्षित एवं आनररक्षित टिकटों को जारी करने हेतु निजी भागीदारी द्वारा यात्री टिकट सुविधा केन्द्र के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

1. कार्य का नाम: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) का आवंटन: रायपुर रेलवे कांसिग गेट के पास, RVM रेलवे कालोनी, द.पू.म. रेलवे रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में इस उद्देश्य के लिए रखे गए आवेदन बॉक्स में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द.पू.म. रेलवे, रायपुर को संबो धित अपने मुहरबंद लिफाफे डाल सकते हैं। अधिक जानकारी, योग्यता मानदंड विभिन्न, स्टेशनों/स्थानों व कार्य का पूर्ण विवरण कृपया वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एसईसी रेलवे रायपुर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं एवं वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध पूर्ण विवरण हासिल कर सकते हैं। आवेदन पत्र / दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्यिक), PR/RSr.DCM/FL/09 द.पू.मध्य रेलवे, रायपुर

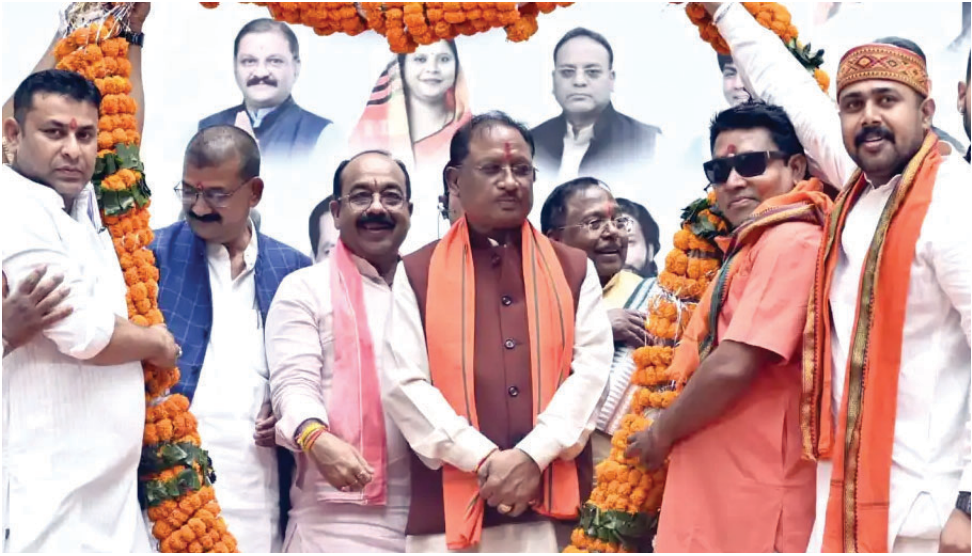
South East Central Railway

रायपुर एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा, किसानों को मिलेगा फायदा-मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नवा रायपुर के सेक्टर-24 में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त अध्यक्षों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर एवं छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कुमार चंद्रवंशी को नए दायित्व के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद की किसानों एवं कृषि के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। खेत तभी लहलहाते हैं जब बीज अच्छा होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज समय पर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि आज पदभार ग्रहण कर रहे दोनों अध्यक्ष स्वयं किसान हैं। वे किसानों की कठिनाइयों को अच्छे से समझते हैं। निश्चित रूप से दोनों अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के दुःख-दर्द को समझती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसानों की उन्नति के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका



लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों की समस्या के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण सुविधा प्रारंभ की गई।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद एवं छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम का किसानों के बेहतर नवाचार एवं नवीन योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार ने ऐसे जमीनी स्तर

से दो बेहद अनुभवी, कुशल संगठक, किसान पुत्र को इसकी जिम्मेदारी दी है। निश्चित ही इसका लाभ प्रदेश के किसान भाइयों को मिलेगा।

कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि भगवान हनुमान की जयंती है। हनुमान जी शक्ति, सामर्थ्य, सेवा एवं समर्पण के प्रतीक हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से हमारी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद एवं छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम का महत्वपूर्ण योगदान कृषि क्षेत्र में है। किसानों को उचित समय सीमा में गुणवत्ता पूर्ण बीज

रायपुर एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा जल्द शुरू होगी। इससे किसानों की उपजों को अंतरराष्ट्रीय मार्केट मिलेगा और उन्हें फायदा होगा। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के अन्नदाता किसान भाई-बहनों से मिलेट्स, मक्का और ऐसी फसलों के उत्पादन का आग्रह किया, जिनमें पानी की खपत कम होती है। उन्होंने कहा कि हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर सुजला योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी, जिसमें किसानों को अनुदान पर सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आग्रह बढ़ाने के लिए किसानों से खेती के साथ-साथ उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों से कहा कि आवास प्लास-प्लास योजना का सर्वोत्तम रहे, इस सर्वे में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि आवास योजना की पात्रता में वृद्धि की गई है। अब जिनके पास 5 एकड़ असिंचित भूमि, ढाई एकड़ सिंचित भूमि है, मोटरसाइकिल है, साथ ही 15 हजार मासिक आय वाले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के पांच वर्षों में गरीबों को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने शपथ लेने के दूसरे दिन हमने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। पिछले 14 माह की अवधि में हमें केंद्र से 14 लाख आवास की राशि मिल गई है। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ को शीघ्र ही साढ़े तीन लाख आवास की राशि और देने जा रहे हैं।

उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही कृषि में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने की भी जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है, चाहे 31 सौ प्रति किलोमीटर में धान खरीदी हो या वनोपज की खरीदी में। इसका ही परिणाम है कि प्रदेश में धान उत्पादन से लेकर अन्य फसल, साग-सब्जियों में कृषि रकबा बढ़ा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर एवं छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष

सुरेश कुमार चंद्रवंशी को नवीन जिम्मेदारी के लिए बधाई दी गई।

इस अवसर पर सांसद रायपुर बृजमोहन अग्रवाल, राजनांदागंव संतोष पांडेय, महासमुंद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक रायपुर ग्रामीण मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर विधायक पुरेंद्र मिश्रा, बसना संपत अग्रवाल सहित विभिन्न मंडल आयोग के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अधिकारी-कर्मचारीगण एवं बड़ी संख्या में किसान बंधु उपस्थित थे।

श्रमिक कल्याण और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री साय



श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के गुडियारी में आयोजित अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के 18वें त्रैवार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिवेशन में 21 राज्यों से आए श्रमवीरों का प्रभु श्रीराम के ननिहाल में स्वागत किया और उन्हें हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि देशभर से आए श्रमवीरों ने यहाँ आकर

एकता और सामंजस्य का बड़ा संदेश देने का कार्य किया है। श्री साय ने कहा कि प्रभु श्रीराम ने 14 वर्षों के वनवास में से 10 वर्ष यहाँ बिताए, जो प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहली सरकार का गठन हुआ था, तब उन्होंने श्रम राज्य मंत्री के रूप में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम

पेंशन निर्धारित की गई और पीएफ की अनकलेम राशि का उपयोग श्रमिकों के हित में किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में बिजली की महत्ता को सभी भली-भाँति समझते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली सरप्लस है, लेकिन आने वाले समय में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में



1350 और 850 मेगावाट की दो विद्युत परियोजनाओं की सौगात दी थी।

श्री साय ने आगे बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये के लिए उनके योगदानों को नमन किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के मंत्री और प्रभारी श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री मधुसूदन जोशी, श्रीमती शोभा सिंहदेव सहित देने की ओर बढ़ रहे हैं और योजना के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी देने का

बजट में प्रावधान भी किया है।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्रमिकों के कल्याण के लिए आजीवन समर्पित रहे श्री दत्तोपंत टेंगड़ी का पुण्य स्मरण करते हुए उनके योगदानों को नमन किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के मंत्री और प्रभारी श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री मधुसूदन जोशी, श्रीमती शोभा सिंहदेव सहित देशभर के 21 राज्यों से आए विद्युत श्रमिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हनुमान जयंती पर की पूजा-अर्चना



श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया तथा प्रदेशवासियों की सुख-शांति और

समृद्धि के लिए मंगलकामनाएं कीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भगवान हनुमान शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से हर संकट का समाधान संभव है। उन्होंने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सर्प्लाईज कार्पोरेशन के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

प्रत्येक जरूरतमंद को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार कर रही है भगीरथ प्रयास : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 670 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में हुए शामिलमुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में हुए शामिलमुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में हुए शामिलमुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में हुए शामिल



बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। पिछले 14 माह के हमारे कार्यकाल में हाउसिंग बोर्ड की स्थिति सुधरी, बोर्ड अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। इस अवधि में हमें केंद्र से 14 लाख आवास भी मिले हैं। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ को शीघ्र ही साढ़े तीन लाख आवास और देने जा रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्री अनुराग को लंबे समय से विपरीत परिस्थितियों में कार्य के लिए जाना जाता है। निश्चित ही उनके अनुभवों का लाभ छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को मिलेगा। उन्होंने इस अवसर पर नव नियुक्त श्री अनुराग सिंहदेव को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान एवं मजदूरों के लिए नित नई योजनाएं बनाकर उनकी बेहतरी के लिए कार्य कर रही है।

हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से भी आम जनता को सहज एवं किफायती दरों में मकान का सपना पूरा हो, इस उद्देश्य से बेहतर कार्य करने के लिए नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव को बधाई दी।

कैबिनेट मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही किफायती मूल्यों में गरीब जनता के लिए आवास तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। हमने पूरे प्रदेश में अधूरी पड़ी लगभग 40 योजनाओं के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया है। पुरानी संपत्तियों की विक्री के लिए हमने 'वन टाइम सेटलमेंट' के नाम से हितग्राहियों को छूट देने का भी कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने 670 करोड़ की लागत की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया उनमें 43.03 करोड़ रुपये की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 626 करोड़ 81 लाख की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने अटल विहार योजनांतर्गत मुरमुदा जिला दुर्ग में 226 भवनों का निर्माण



एवं 10.00 एकड़ भूमि का विकास कार्य लागत 2457.98 लाख रुपये, अटल विहार योजनांतर्गत कोतापाल जिला बीजापुर में 183 भवनों का निर्माण एवं 5.73 एकड़ भूमि का विकास कार्य लागत 1845.32 लाख रुपये का लोकार्पण किया।

इसी तरह अटल विहार योजनांतर्गत पथरां राजिम जिला रायचूर में 363 भवनों एवं 8.307 हेक्टेयर भूमि का विकास कार्य लागत 6168.53 लाख रुपये, अटल विहार योजना भूकोनी जिला रायपुर में 345 भवनों का निर्माण एवं 14.00 एकड़ भूमि का विकास कार्य लागत 6103.59 लाख रुपये, सामान्य आवास योजनांतर्गत सेक्टर-12, नया रायपुर जिला रायपुर में 1052 भवनों एवं व्यवसायिक परिसर का निर्माण एवं 28.04 हेक्टेयर भूमि विकास कार्य लागत 31054.56 लाख रुपये, अटल विहार योजनांतर्गत पुलगांव जिला दुर्ग में 18 सौ निगय एच.आई.जी. डुप्लेक्स, 31 एच.आई.जी. डुप्लेक्स, 69

एम.आई.जी. डुप्लेक्स, 64 एल. आई. जी. 95 ई.डब्ल्यू.एस. कुल 277 स्वतंत्र भवनों का निर्माण एवं यूटिलिटी शॉप एवं 17.94 एकड़ भूमि का विकास कार्य लागत 10311.80 लाख रुपये, अटल विहार योजनांतर्गत खरतुली जिला धमतरी में 182 भवनों का निर्माण एवं 9.39 एकड़ भूमि का विकास कार्य लागत 2699.70 लाख रुपये, अटल विहार योजनांतर्गत कोकड़ापारा जिला बीजापुर में 183 भवनों का निर्माण एवं 7.89 एकड़ भूमि का विकास कार्य लागत 2978.33 लाख रुपये, अटल विहार योजनांतर्गत बंधी जिला गौरेला - पेण्ड्रा - मरवाही में 135 भवनों का निर्माण एवं 6.50 एकड़ भूमि का विकास कार्य लागत 2101.65 लाख रुपये, अटल विहार योजनांतर्गत कुलीपोटा जिला जांजगीर - चांपा में 61 भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य लागत 1260 लाख रुपये की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया।